दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 13 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 107

महत्वपूर्ण एवं खास

एक करोड़ रुपए से अधिक का पीडीएस खाद्यान्न गायब, गोदाम सील

पोरबंदर (आरएनएस)। गुजरात के पोरबंदर में एक पीडीएस गोदाम से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का खाद्यान्न गायब हो गया, जिसके बाद सरकार ने गोदाम को सील कर दिया। पोरबंदर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गोदाम को सील कर दिया है, आंतरिक जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी हीराल देसाई ने मीडियाकर्मियों को बताया, रनवाव पीडीएस गोदाम से करीब 7000 बैग गेहूं और चावल गायब हैं, जिनकी कीमत एक करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये के बीच है। इसलिए, गोदाम को सील कर दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले सप्ताह में निरीक्षण के लिए आए थर्ड पार्टी ऑडिटर ने गड़बड़ी देखी। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने पाया कि वास्तविक स्टॉक और रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़े बेमेल हैं, जिसके बाद ऑडिटर ने तुरंत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। पोरबंदर की उप प्रबंधक उषाबेन भोये ने दावा किया है कि उन्होंने दिसंबर में ही बेमेल नोटिस किया था और दिसंबर में ही रिपोर्ट दर्ज की थी

फर्जी दस्तावेज जमा करने पर 40 छात्रों पर कार्यवाई

गोरखपुर (आरएनएस)। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय (एमएमएमटीयू) ने फर्जी प्रमाणपत्रों के कथित उपयोग को लेकर विभिन्न शाखाओं के 40 बी.टेक छात्रों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है। एमएमएमटीयू के कुलपति जेपी पांडे ने कहा कि तीन सदस्यीय जांच रिपोर्ट में कदाचार की पुष्टि के बाद 40 छात्रों का प्रवेश रद्द कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यह मामला पहली बार पिछले साल सितंबर में सामने आया था, जब विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने पाया कि एक लडक़ी ने प्रवेश शुल्क की फर्जी रसीद पेश की थी। इसके बाद उसका प्रवेश आवंटन नंबर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भेजा गया और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। जांच के दौरान प्रवेश प्रक्रिया में घोर अनियमितता सामने आई। जांच रिपोर्ट के बाद अकादमिक परिषद ने 2020-21 और 2021-22 बैच के 40 बीटेक छात्रों के प्रवेश को निलंबित करने की सिफारिश की।

20 साल से बिस्तर पर पड़ी महिला पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज

मेरठ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 20 साल से बिस्तर पर पड़ी एक महिला पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 53 वर्षीय महिला अलीशा बेगम 20 वर्षों से दृष्टि हानि सहित कई स्वास्थ्य विकारों के कारण बिस्तर पर पड़ी हैं। उसका वजन लगभग 130 किलो है और वह खुद चल नहीं सकतीं। पुलिस रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि वह एक गैंगस्टर है। खबरों के मुताबिक अलीशा के पति 53 वर्षीय मोहम्मद हनीफ के कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय व्यवसायी नसीम कुरैशी के साथ व्यापारिक संबंध हैं। नवंबर 2021 में कुरैशी ने हनीफ के खिलाफ 3.5 करोड़ रुपये वापस नहीं करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाने के बावजूद 13 दिसंबर, 2022 को अलीशा सहित परिवार के छह सदस्यों पर गैंगस्टर अधिनियम लगाया गया।

जोशीमठ आपदा : सेना की बैरकों तक पहुंची दरारें

❐ स्टैंड बाई पर आईटीबीपी की 3 कंपनियां

जोशीमठ (आरएनएस)। उत्तराखंड के 'धंसते शहर' जोशीमठ में सेना के कुछ बैरकों में दरार आई है। इसके चलते कुछ जवानों को ऊपर के दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। गनीमत है कि इस आपदा से सेना का ब्रिगेड हेड चर्टर फिलहाल सुरक्षित है। बावजूद इसके बॉर्डर रॉड्स, सेना और आईटीबीपी की हालात पर पूरी नजर है। उधर, सूचना मिलने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बुधवार को जोशीमठ पहुंचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक जोशीमठ में भू धंसाव से पैदा हुए खतरे का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस भू धंसाव के चलते जोशीमठ स्थित सेना के कई बैरकों में भी दरार आ गई है। यह दरार उन बैरकों में ज्यादा देखी जा रही है जो नदी के करीब हैं। गनीमत

है कि इस आपदा का सेना के बिग्रेड हेड चर्टर पर अब तक कोई असर नहीं पड़ा है। सेना का बिग्रेड हेड चर्टर ऊंची पहाड़ी पर है। ऐसे में प्रभावित बैरकों में रह रहे जवानों को ऊपर की बैरकों में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार आईटीबीपी का बटालियन भी अभी तक इस आपदा से पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि हालात पर नजर रखने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आईटीबीपी की तीन कंपनी स्टैंड बाई पर रखा गया है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जोशीमठ आपदा का ज्यादा असर निचले इलाकों में ही है। इन्हीं इलाकों में बनी सडक़ों या जमीन के धंसने की सूचना है। इसी प्रकार सेना के भी उन्हीं बैरकों को नुकसान पहुंचा है जो निचले हिस्से में होने के साथ ही नदी के करीबी इलाकों में हैं। ऐसे हालात में सेना ने भी अपनी ओर से राहत और बचाव कार्य के साथ अपने साजो सामान की सुरक्षा के लिए अलर्ट हो गई है।

जोशीमठ में होटलों को गिराया जाना शुरू, अमित शाह ने बुलाई हाईलेवल बैठक

असंख्य भवनों में आई दरारों के बाद असुरक्षित इमारतों को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक कुल 678 भवन चिह्नित किए जा चुके हैं। सीबीआरआई की टीम ने मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया था। आज बृहस्पतिवार को होटल माउंट व्यू को ढहाया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिन रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि वहां एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं। इलेक्ट्रिक केबल और पोल्स की सुरक्षा के लिए 2.14 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहां एनडीआरएफ की दो टीमें भी मौजूद हैं और एक टीम देरशाम पहुंचेगी। आर्मी और आपदा प्रबंधन के हेलिकॉप्टर को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालातों को देखते हुए गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र शेखावत सहित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके पहले भी बुधवार को अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत के जरिए जोशीमठ के हालात जाने थे। केंद्रित गृह मंत्रालय और अमित शाह जोशीमठ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह ने गुरुवार को जोशीमठ संकट को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला, बीआरओ और एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जोशीमठ में हो रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी साझा की गई है। इसके अलावा आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

आपदा की घड़ी में जनता एवं प्रशासन समन्वय बनाकर काम करें : सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा की घड़ी में जोशीमठ की जनता एवं प्रशासन आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें तो इस संकट से उभर जाएंगे। धामी ने जोशीमठ संकट से उभरने और राहत बचाव कार्य तथा जीवन व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है।

उन्होंने सभी को आपदा की इस घड़ी में प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की जान माल की सुरक्षा करते हुए उनके लिए आगे का रास्ता बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान, दुकान, व्यवसाय प्रभावित हुए है उन सभी को अंतरिम सहायता के रूप में 1.50 लाख तत्कालीन सहायता के रूप से दिए जा रहे है। अभी यह पूरा राहत पैकेज नही है। इसके लिए यहां पर समिति गठित कर दी गई है और प्रभावित लोगों को बेहतर से बेहतर राहत दी जाएगी और उनके पुनर्वास के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग जोशीमठ को लेकर दहशत का माहौल बना रहे है जो कि गलत है। इससे हमारे लोगों एवं प्रदेश का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इसलिए ऐसा महौल न बनाए और सबको मिलकर पीडितों की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में भूधंसाव कारणों का पता लगाया जा रहा है। जेपी कंपनी के पास जो पानी का रिसाव हुआ था वह भी अब कम हो रहा है। इससे पहले धामी ने जोशीमठ के आराध्य देवता भगवान नृसिंह की विशेष पूजा भी की और जोशीमठ के सुरक्षित रहने की कामना की।

फर्जी समाचारों पर केंद्र सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, 6 यूट्यूब चैनल ब्लॉक

नई दिल्ली (आरएनएस)। फर्जी समाचार फैलाने और भ्रामक जानकारी देने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ केंद्र सरकार का कड़ा रुख बरकरार है। केंद्र सरकार ने इस मामले में गुरुवार को छह यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया। ब्लॉक किए गए सभी चैनलों ने चुनावों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत की संसद में कार्यवाही और भारत सरकार के कामकाज के बारे में गलत खबर और भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पीआईबी की ओर से बताया गया कि ये यूट्यूब चैनल दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी चैनलों के टेलीविजन समाचार एंकरों के नकली, क्लिकबेट और सनसनीखेज थंबनेल और छवियों का उपयोग करते हैं। संवाद टीवी नाम से चल रहे एक यूट्यूब चैनल के 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। इस चैनल के जरिए भारत सरकार और केंद्रीय मंत्रियों

के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा रही थीं। इन चैनलों ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कई प्रमुख टीवी चैनलों के एंकरों की तस्वीर, क्लिकबेट और सनसनीखेज थंबनेल का प्रयोग करते थे। चैनलों ने इसका प्रयोग उनके द्वारा डाले गए वीडियो को मोनेटाईज करने और ट्रैफिक लाने के लिए कर रहे थे। केंद्र ने इस तरह की यह दूसरी कार्रवाई की है। इससे पहले सरकार ने 20 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें फर्जी खबर फैलाने वालों तीन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

सदन में हंगामा करने वाले सांसदों व विधायकों के लिए बनेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के जयपुर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में सदन में हंगामा करने वाले सांसदों और विधायकों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने, न्यायपालिका को संवैधानिक मर्यादा का पालन करने और जी-20 एवं पी-20 से जुड़े कार्यक्रमों सहित कुल नौ प्रस्तावों को पारित किया गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कानून बनाने के मामले में विधायिका सर्वोच्च है। न्यायालय के पास कानून की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है लेकिन न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक मयार्दा का पालन करना चाहिए और हर कानून की समीक्षा के

लिए पीआईएल उचित नहीं है। बिरला ने कहा कि इसके साथ ही पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि सदन में हंगामे को रोकने के लिए संसद और देश की विभिन्न विधानसभाओं में बने अच्छे नियमों को एक साथ लाकर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए।

इससे पहले समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने सदैव विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधान मंडलों में आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेज साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं।

उन्होंने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में विधान मंडलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। विधायी निकायों में सार्थक, अनुशासित और उत्पादक चर्चा पर जोर देते हुए बिरला ने कहा कि सदनों में अधिकतम संवाद हो, तकनीक का सही उपयोग हो और जनता और विधायिका का जुड़ाव सशक्त हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्व नियोजित संगठित व्यवधान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विधायिकाओं में नियमों और प्रक्रियाओं की एकरूपता की आवश्यकता को दोहराते हुए बिरला ने कहा कि वित्तीय स्वायत्तता के बावजूद, नियमों और प्रक्रियाओं की एकरूपता संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेगी। उन्होंने संसदीय समितियों को और मजबूत करने की वकालत करते हुए कहा कि संसदीय समितियों में दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने की उत्कृष्ट परंपरा है। वे मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं।

भारत की जी-20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि ये दुनिया को भारत के लोकतंत्र के बारे में बताने का अवसर है, अपनी क्षमताओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने का अवसर है। जी- 20 तथा इन देशों की संसदों के अध्यक्षों का पी-20 सम्मेलन हमारे लिए मात्र एक राजनयिक आयोजन नहीं होगा बल्कि इसमें जन जन की भागीदारी होगी। उन्होंने शांति और विकास के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया।

तकनीकी खराबी के कारण अमेरिका में 10 हजार उड़ानों में देरी, 1300 रद्द

वाशिंगटन। देश के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के अनुसार राष्ट्रव्यापी तकनीकी गड़बड़ी के कारण अमेरिका के भीतर और बाहर लगभग 10 हजार उड़ानों में देरी हुई, जबकि 1,300 से अधिक अन्य को रद्द कर दिया गया। बुधवार का व्यवधान क्षतिग्रस्त डेटाबेस फाइल के कारण था, और कहा कि इस समय साइबर हमले का कोई सबूत नहीं है। हालांकि सामान्य हवाई यातायात संचालन धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहा है।

गौरतलब है कि तकनीकी कारणों से लगभग दो दशक में पहली बार अमेरिका में उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति मामले की जांच का आह्वान किया है।

इस बीच परिवहन सचिव पीट बटिगिएग ने सीएनएन को बताया कि

एफएए ने अपने नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में अनियमितताओं को देखने के बाद सावधानी के साथ उड़ान भरी।

बटिगिएग ने कहा, अब मेरी प्राथमिकता ऐसी घटनाएं, दोबार न हो, यह सुनिश्चित करना है।

प्रमुख अमेरिकी एयरलाइंस ने कहा कि वे स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। वह एफएए के साथ काम कर रहा है, ताकि ग्राहक व्यवधान को कम किया जा सके। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि वह 16 जनवरी को या उससे पहले उड़ान भरने वाले ग्राहकों के लिए परिवर्तन शुल्क और किराए में किसी भी अंतर को माफ कर देगी। डेल्टा ने कहा कि वह जल्द से जल्द अपडेट प्रदान करेगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर कनाडा ने कहा कि आउटेज बुधवार को सीमा पार संचालन पर असर डालेगा, लेकिन शुरुआत में यह नहीं कह सकता कि किस हद तक।

इस बीच पेरिस के हवाई अड्डों चार्ल्स डी गॉल और ओरली ने कहा कि उन्हें अमेरिकी उड़ानों में देरी की उम्मीद है और एयर फ्रांस ने कहा कि वह स्थिति की निगरानी कर रहा है।

यूके के यात्रियों के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने कहा कि अमेरिका के लिए और अमेरिका से इसकी उड़ानें योजना के अनुसार संचालित होंगी और वर्जिन अटलांटिक ने कहा कि यह यूके से प्रस्थान करने वाली अमेरिकी उड़ानों के अपने शेड्यूल को संचालित करना जारी रखे हुए है।

हालांकि कुछ अमेरिकी प्रस्थान एयरलाइन ने कहा कि देरी से प्रभावित हो सकते हैं।

जर्मनी के लुफ्थांसा और स्पेन के इबेरिया ने कहा कि वे अभी भी सामान्य रूप से अमेरिका से आने-जाने के लिए उड़ानें संचालित कर रहे हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो ने छापेमारी कर की बिना आई.एस.आई मार्क खिलौनों की जब्ती

सीकर (आरएनएस)। भारतीय मानक ब्यूरो, राजस्थान की टीम द्वारा 12 जनवरी को सीकर शहर के स्टेशन रोड पर स्थित मेसर्स टॉय हाउस नामक दुकान पर छापेमारी की कार्यवाही की गई और बड़ी संख्या में बिना आई. एस. आई मार्का और घटिया क्वालिटी के खिलौने जब्त किए गए, जिनमें ज्यादातर खिलोने मेड इन चाइना पाए गए।

उल्लेखनीय है कि ग्राहक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा खिलौनो को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (बीआईएस एक्ट 2016) और खिलौनो से सम्बंधित भारत सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार बिना आईएसआई मार्क के खिलौनों को बेचना दंडनीय अपराध है और उपरोक्त विक्रेता द्वारा इस आदेश का उल्लंघन होता हुआ पाया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर इस तरह की कई मुहिम चलाई जाती है। इससे पहले भी जयपुर और अलवर में घटिया खिलौनों पर इस तरह की ज़ब्ती कार्यवाही की जा चुकी है । ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर पर बीआईएस केयर एप भी लॉच किया गया है। जिससे ग्राहक स्वयं ही न केवल आई.एस.आई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क लाइसेंस के विवरण को सत्यापित कर सकते हैं बल्कि बीआईएस हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को भी सत्यापित कर उसकी प्रामाणिकता जान सकते है। इसी एप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधी शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है।

रामसेतु राष्ट्रीय धरोहर : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने 'रामसेतु' को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को फरवरी के पहले सप्ताह तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद डॉ. स्वामी की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद सरकार को फरवरी के प्रथम सप्ताह तक अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में करेगी।

डॉ. स्वामी ने पीठ के समक्ष

दलील देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने 12 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को वचन दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अदालत के समक्ष दिये गये वचन का पालन नहीं करने पर केंद्रीय कैबिनेट सचिव को समन जारी करने की मांग की , लेकिन पीठ ने उनकी इस गुहार को अस्वीकार कर दिया। डॉ. स्वामी ने भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद खाड़ी में तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित चट्टानों से निर्मित 'रामसेतु' को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करते हुए 2007 में एक याचिका दायर की थी।

हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले बहुत से लोगों का मानना है कि ये चट्टानें रामायण काल की हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में यह पता लगाने के लिए शोध की अनुमति दी थी कि रामसेतु मानव निर्मित है या नहीं। इसके अलावा इसके बनने का समय क्या है और क्या यह रामायण के दौर से मिलता है।

पाकिस्तान पर मंडरा रहा भुखमरी का खतरा

इस्लामाबाद। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) पाकिस्तान को जीने की बढ़ती लागत के बीच भुखमरी के एक बड़े खतरे का सामना करते हुए देख रहा है। इसने चेतावनी दी है कि यह प्राकृतिक आपदाओं और बाधित आपूर्ति से और बढ़ सकता है। पाकिस्तान के बारे में, रिपोर्ट बताती है कि मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदा और बाधित आपूर्ति का संयोजन लाखों लोगों के लिए भुखमरी के मौजूदा संकट को एक विनाशकारी में ले जा सकता है।

ऊर्जा की कमी (आपूर्तिकर्ता के बंद होने या प्राकृतिक, आकस्मिक, या पाइपलाइनों और ऊर्जा ग्रिड को जानबूझकर नुकसान के कारण) मौसमी आपदा के साथ संयुक्त होने

पर व्यापक ब्लैकआउट और घातक परिणाम हो सकते हैं।

डब्ल्यूईएफ के पार्टनर्स इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमी एंड सोसाइटीज प्लेटफॉर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिशाल पाकिस्तान, आमिर जहांगीर ने कहा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 कहती है कि पाकिस्तान के लिए, बुनियादी जरूरतों की सामथ्र्य और उपलब्धता दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

उन्होंने कहा, असुरक्षा का प्रभाव पाकिस्तान में महसूस किया जाना जारी रहेगा और एक साथ खाद्य और ऋण संकट के कारण अस्थिरता को भी बढ़ा सकता है, जिसके चलते संभावित तकनीकी-आधारित निर्णय लेने वाले नेतृत्व ढांचे का उदय होगा।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट बताती है कि जीवन-यापन का संकट सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम है जबकि जलवायु शमन और जलवायु अनुकूलन की विफलता सबसे बड़ी दीर्घकालिक चिंता है।

भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अंतमुर्खी रुख आर्थिक बाधाओं को बढ़ाएंगे और शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म दोनों जोखिमों को और बढ़ाएंगे।